



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27 ]  
No. 27]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 1999/वैशाख 6, 1921  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 1999/VAISAKHA 6, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1999

सं. 8/1/99-के. वि. वि. आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 14) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय-1

साधारण

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा निवर्त्तन :—

- (क) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 है।  
(ख) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।  
(ग) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।

परिभाषा

- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—  
(क) "अधिनियम" से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 14) अभिप्रेत है।  
(ख) "आयोग" से अधिनियम के अधीन गठित केन्द्रीय आयोग अभिप्रेत है।  
(ग) "अधिकारी" से इस आयोग का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।  
(घ) "याचिका" से सभी याचिकाएं, आवेदन, परिवाद, अपीलें, उत्तर, प्रत्युत्तर, अनुपूरक अभिवचन, अन्य कागज-पत्र तथा दस्तावेज अभिप्रेत हैं।  
(ङ) "कार्यवाही" से वे सभी कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत वे सभी प्रकार की कार्यवाहियां आती हैं जो अधिनियम के अधीन आयोग, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कर सकता है।  
(च) "विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 अभिप्रेत है।  
(छ) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत है।

2. इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में वे परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।
3. समय-समय पर यथासंशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1997 के उपबन्ध इन विनियमों को लागू होंगे।

#### आयोग का कार्यकाल, कार्यालय समय तथा बैठकें :

3. आयोग के कार्यालयों का स्थान आयोग द्वारा इस निमित्त समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
4. जब तक अन्यथा निर्देशित न किया जाए तब तक आयोग का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय शनिवार, रविवार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय सरकार की शूटिंगों के अतिरिक्त प्रतिदिन खुले रहेंगे। आयोग के मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय ऐसे समयों पर भी खुले रहेंगे जैसा आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्देश दिया जाए।
5. जहाँ कोई अंतिम कार्यालयस ऐसे दिन पड़ता है जिसको आयोग का कार्यालय बन्द रहता है तथा इस कारण उस दिन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है तो वहाँ वह कार्य अगले कार्यालयस को किया जाएगा जिस दिन कार्यालय खुलता है।
6. आयोग मामलों की सुनवाई के लिए बैठकें मुख्यालय अथवा किसी अन्य स्थान, दिन और समय पर आयोजित कर सकेगा जैसा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

#### आयोग की भाषा :

7. आयोग की कार्यवाहियाँ, यदि आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाता है तो अंग्रेजी या हिन्दी में संचालित की जाएँगी।
8. यदि आयोग द्वारा अनुज्ञा दी जाती है तो अंग्रेजी अथवा हिन्दी से भिन्न अन्य किसी भी भाषा में कोई याचिका, दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी जब इनका अंग्रेजी/हिन्दी में अनुवाद संलग्न किया गया हो।
9. कोई भी अनुवाद जिसके लिए कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा सहमति दी जाती है अथवा कोई भी पक्षकार उस व्यक्ति का, जिसने उसका अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद किया था, अधिग्रामाणिकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आयोग द्वारा उसे सही अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।
10. आयोग, उपयुक्त मामलों में याचिका, अभिव्यक्ति, दस्तावेजों तथा अन्य सामग्री के अंग्रेजी अनुवाद के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा पदाधिकारी या व्यक्ति को इसके अनुवाद के लिए निदेश दे सकेगा।

#### आयोग की मुद्रा:

11. आयोग की पृथक से मुद्रा होगी, जो यह उपर्युक्त करेगी की वह मुद्रा उसकी है।

#### आयोग के अधिकारी :

12. (1) आयोग को भिन्न-भिन्न कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी। यह ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अहताएं, अनुभव तथा अन्य निबंधन और शर्तें भी विहित कर सकेगा।
- (2) आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आयोग को सहयोग देने के लिए सलाहकार की नियुक्ति कर सकेगा। सलाहकारों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें समय-समय पर आयोग की बैठकों द्वारा विहित की जाएंगी।
13. (1) आयोग का प्रमुख अधिकारी सचिव होगा तथा वह अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (2) अधिनियम के अधीन आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जैसा वह उपयुक्त समझेगा सचिव से सहयोग लेगा तथा सचिव आयोग को सहयोग देने के लिए बाध्य होगा।
- (3) सचिव को उपर्युक्त उपबन्धों की व्यापकता पर विशिष्टतया और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—
  - (क) वह आयोग के अभिलेख तथा मुद्रा की अभिव्यक्ति करेगा।
  - (ख) वह आयोग से संबंधित सभी याचिकाओं, आवेदनों अथवा संदर्भ को प्राप्त करेगा अथवा करवाएगा।
  - (ग) वह इस संबंध में आयोग को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में इसके समक्ष के प्रत्येक मामले में विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी अभिव्यक्तियों का संकेत तथा सारांश तैयार करेगा अथवा करवाएगा।
  - (घ) वह आयोग द्वारा प्रयोग शक्तियों से संबंधित कार्यवाही में आयोग का सहयोग करेगा।
  - (ङ) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिग्रामाणित करेगा।

(च) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।

(छ) वह केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य कार्यालयों, कम्पनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षकार से आयोग द्वारा यथा-निर्देशित ऐसी जानकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझा जाता है, एकत्र करने का अधिकारी होगा तथा जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

14. आयोग, अपने अधिकारियों को ऐसे कृत्य, जिसके अंतर्गत विनियमों के अधीन सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य कृत्य भी हैं, ऐसे निबंधन और शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा औसी आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाएँ ।

15. सचिव, आयोग के अनुमोदन से इन विनियमों अथवा अन्यथा सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य अपेक्षित किसी भी कृत्य को किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

16. सचिव की अनुपस्थिति में, आयोग का ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारित किया जाए, सचिव के सभी कृत्यों का प्रयोग करेगा ।

17. आयोग को हर समय यह प्राधिकार होगा कि वह किसी भी समय या तो किसी हितबद्ध अथवा प्रभावित पक्षकार से प्राप्त आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से यदि आयोग ऐसा किया जाना उपयुक्त समझता है, सचिव द्वारा अथवा आयोग के अधिकारियों द्वारा किए गए किसी आदेश अथवा की गई कार्रवाई का पुनर्विलोकन, प्रतिसंहरण, पुनरीक्षण, उपानारण, संशोधन, परिवर्तन अथवा अन्यथा परिवर्तन कर सकेगा ।

**उपभोक्ता संगमों के लिए मान्यता :**

18. (1) आयोग किसी भी संगम/फोरम अथवा अन्य निगमित निकायों या उपभोक्ताओं के किसी भी समूह को आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दे सकेगा ।

(2) आयोग, कार्यवाही को समय पर पूरा करने की दृष्टि से ऊपर निर्दिष्ट संगमों/फोरम को इकट्ठा होने के लिए निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा जिससे कि वे सामूहिक रूप से शपथपत्र दे सकें ।

(3) आयोग, जब कभी भी यह उचित समझे संगमों, समूहों, फोरम अथवा निगमित निकायों को, आयोग के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संगम के रूप में मान्यता के लिए प्रक्रिया अधिसूचित कर सकेगा ।

19. (1) आयोग, यदि आवश्यक समझे तो वह उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

(2) आयोग, उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त अधिकारी अथवा व्यक्ति को ऐसी फीस, लागत या खर्च के भुगतान के लिए ऐसा निदेश दे सकेगा जैसा आयोग उपयुक्त समझे और जो कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा वहन किया जाएगा ।

### अध्याय-2

#### आयोग के समक्ष कार्यवाहियों से संबंधित साधारण नियम

##### आयोग के समक्ष कार्यवाहियों, आदि :

20. आयोग, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए जैसा वह उचित समझे, समय-समय पर, सुनवाई, बैठकें, विचार-विमर्श, शिवेषना, जांच, अन्येषण तथा परामर्श करेगा ।

##### गणपूर्ति :

21. आयोग के समक्ष कार्यवाही के लिए गणपूर्ति की संख्या तीन होगी ।

##### सदस्यों की उपस्थिति तथा मतदान :

22. कोई सदस्य, पटेन सदस्य सहित किसी नियन्त्रण पर अपने मत का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि ऐसे मामले में वह आयोग की सारान्न मुनवाई के दौरान उपस्थित न रहा हो ।

##### प्रतिनिधित्व का प्राधिकार :

23. कोई व्यक्ति, आयोग के समक्ष अपना पक्ष समर्थन अपनी ओर से कार्य करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट रीति से किसी अधिवक्ता या किसी कानूनी वृत्तिक निकाय के ऐसे सदस्य को जो कि विधिक व्यवसाय का प्रमाण-पत्र रखता हो, प्राधिकृत कर सकेगा । कोई व्यक्ति आयोग के समक्ष स्वयं भी उपसंजात हो सकेगा या अपनी ओर से अपने किसी कर्मचारी को उपसंजात होने और कार्य करने या अभिवचन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । आयोग, समय-समय पर, ऐसे निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने और कार्य करने तथा अभिवचन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

### कार्यवाहियों का शुरू होना :

24. आयोग, स्वतः: अधिका किसी प्रभावित या हितवद्ध व्यक्ति द्वारा फाइल की गई याचिका पर कार्यवाही शुरू कर सकेगा।
25. आयोग, कार्यवाही शुरू करने का नोटिस जारी कर सकेगा तथा आयोग, यदि आवश्यक समझे तो प्रभावित पक्षकारों को ऐसे नोटिस की तामील के लिए, उत्तर फाइल करने के लिए और याचिका के पक्ष या विषय में उत्तर तथा प्रत्युत्तर उपयुक्त प्रस्तुति में फाइल किये जाने के निदेश भी दे सकेगा। आयोग यदि उचित समझे तो कार्यवाही के मामले पर टीका टिप्पणियां ऐसे प्रस्तुति में जैसा आयोग निदेश दे, आंमत्रित करते हुए याचिका के प्रकाशन के लिए आदेश जारी कर सकेगा।
26. आयोग उचित भामलों में जाँच के नोटिस जारी करते समय आयोग के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे आयोग मामले में याचिकाकर्ता के रूप में भामले को प्रस्तुत करने के लाए उचित समझे, निर्दिष्ट कर सकेगा।

### आयोग के समझ याचिका तथा अभिव्यक्ति :

27. आयोग के समझ फाइल की जाने वाली सभी याचिकाएँ टाइप, साइबरोस्टाइल या सफेद कागज के एक ओर पठनीय तथा साफ प्रिंट की हुई होनी चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ क्रम से संख्यांकित होना चाहिए। आयोग कम्प्यूटर डिस्क या इलैक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नियंत्रित तथा शर्तों पर याचिका फाइल करने की स्वीकृति दे सकेगा। याचिका की विषय-वस्तु अलग-अलग पैरा में समुचित रूप से प्रिभावित होनी चाहिए, जोकि क्रम से संख्यांकित हो। याचिका के साथ समर्थन में वह दस्तावेज, समर्थक डाटा, विवरण संलग्न होने चाहिए जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट करे।

### साधारण शीर्षक :

28. आयोग के समझ सभी याचिकाओं के और सभी प्रकाशनों तथा भोटिसों के साधारण शीर्षक प्रस्तुति-1 में होंगे।

### समर्थन में शपथ-पत्र :

29. (1) याचिकाएँ शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित की जाएंगी तथा ऐसा प्रत्येक शपथ-पत्र प्रस्तुति-2 में होगा।
- (2) सभी शपथ-पत्र एकवचन में लिखे जाने चाहिए तथा पूरा नाम, उम्र, व्यवसाय और अभिसाक्षी का पता तथा वह हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है तथा जिस हैसियत में शपथ पत्र लेने के लिए तथा प्राप्त करने के लिए वैधानिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समझ हस्ताक्षरित तथा शपथित किए जा सकेंगे, का विवरण होना चाहिए।
- (3) प्रत्येक शपथ पत्र में कथन स्पष्टतः तथा अलग से यह उपदर्शित करेंगे कि उसमें—
  - (क) अभिसाक्षी के ज्ञान के अनुसार,
  - (ख) अभिसाक्षी को प्राप्त जानकारी के अनुसार, तथा
  - (ग) अभिसाक्षी के विश्वास के अनुसार सत्य है।
- (4) शपथ पत्र में जहाँ किसी कथन को अभिसाक्षी को प्राप्त सूचना के अनुसार सत्य कहा गया हो, शपथ पत्र सूचना के स्रोत भी प्रकट करेगा तथा एक कथन भी संलग्न करेगा कि अभिसाक्षी को विश्वास है कि उक्त जानकारी सत्य है।

30. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 के अनुसार जो कोई आयोग की किसी भी कार्यवाही में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी कार्यवाही में प्रयोग के प्रयोजन से गलत साक्ष्य गढ़ेगा, वह कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुमानी का भी दायी होगा।

### प्रस्तुतीकरण तथा याचिकाओं की जाँच :

31. सभी याचिकाओं की सात प्रतियाँ फाइल की जाएंगी तथा याचिका का प्रत्येक सेट सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। याचिका के साथ संदेश फीस आयोग द्वारा विहित की जाएगी।
32. सभी याचिकाएँ व्यक्तिगत रूप से या सभी प्राधिकृत अधिकार्ता या प्रतिनिधि द्वारा मुख्यालयों में या आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए ऐसे अन्य फाइलिंग केन्द्र या केन्द्रों पर नियत समय के दौरान प्रस्तुत की जाएंगी। आयोग को याचिकाएँ ऊपर उल्लिखित स्थानों पर रजिस्टर्ड छाक पावरी द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। यदि यह मामले अभिलेख पर पहले से दर्ज न किए गए हों तो प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा याचिका प्रस्तुत करते समय अधिकृता के पक्ष में वकालतमामा तथा याचिका के साथ प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज भी फाइल किए जाने चाहिए।
33. याचिका प्राप्ति पर, याचिका प्राप्ति के प्रायोजन के लिए पदाधिकृत आयोग का अधिकारी मुहर लगाकर तथा जिस तारीख को याचिका प्रस्तुत की गई वह तारीख छालकर पावरी देगा तथा याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को मुहर और तारीख के साथ प्राप्ति सूचना भी देगा। याचिका

यदि रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त होती है तो जिस तारीख को याचिका आयोग के कार्यालय में वास्तविक रूप से प्राप्त होगी वही तारीख याचिका के प्रस्तुतीकरण की तारीख मानी जाएगी।

34. याचिका के प्रस्तुतीकरण तथा प्राप्ति की प्रविष्टि आयोग के कार्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे गए रजिस्टर में सम्यक् रूप से की जाएगी।

35. प्राप्तकर्ता अधिकारी किसी ऐसी याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है जो अधिनियम या विनियमों के उपर्युक्त या आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसर नहीं है या कोई अन्य त्रुटि है या जो विनियमों या आयोग के निर्देशों के अनुसार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से प्रस्तुत की गई है:

परंतु किसी याचिका को, याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए दिए गए समय में शुटी सुधार का अवसर दिए जाए, अभिव्यक्तियों में या प्रस्तुतीकरण में शुटियों की वजह से नामंजूर नहीं किया जाएगा। प्राप्तकर्ता अधिकारी फाइल की गई याचिका में की गई शुटियों को, याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित करेगा।

36. याचिका के प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्राप्तकर्ता अधिकारी के किसी आदेश से व्यक्तित्व यह प्रार्थना कर सकता है कि मामले को समूचित आदेशों के लिए आयोग के संचिव के सम्मुख रखा जाए।

37. अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, जिसे अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए पदाधिकारी करे, पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका मंगाने का हकदार होगा तथा याचिका के प्रस्तुतीकरण और मंजूरी से संबंधित ऐसे निवेश दे सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

38. यदि जाँच करने पर, याचिका नामंजूर नहीं की जाती अथवा संचिव या अध्यक्ष या इस प्रयोजन के लिए आयोग के पदाधिकारी सदस्य द्वारा नामंजूरी के किसी आदेश को परिशोधित किया जाता है तो याचिका सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाएगी तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में एक नम्बर दिया जाएगा।

39. ऐसे ही याचिका तथा सभी आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तथा शुटियों और आपत्तियों, यदि कोई हों तो, दूर की जाती हैं तथा याचिका की जाँच कर ली गई हो तथा उसे संखांकित कर दिया गया हो तो याचिका प्रारंभिक सुनवाई तथा स्वीकृति के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

40. आयोग, पक्षकार की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना भी याचिका को स्वीकृत कर सकता है। आयोग सम्बद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना स्वीकृति रद्द करने के आदेश पारित नहीं करेगा। आयोग यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें वह चाहे याचिका की सुनवाई के लिए, नोटिस जारी कर सकता है।

41. यदि आयोग, याचिका स्वीकार करता है तो प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थियों) तथा अन्य प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे प्रलिप्तों में जिन्हें आयोग निर्दिष्ट करे, याचिका के पक्ष या विपक्ष में उत्तर तथा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए, नोटिस तामील करने के लिए तथा याचिका को यथास्थिति, आयोग/न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखने के ऐसे आदेश तथा दिनेश दे सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

आयोग द्वारा जारी नोटिस तथा आदेशिका तामील करना :

42. (1) आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी आदेशिका या आदेशिका या सम्मन की तामील, आयोग द्वारा निर्देशित निम्न प्रकारों में से किसी एक या अधिक प्रकार से की जा सकेगी :

(क) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा तामील इस प्रकार की जाएगी ऐसी आयोग द्वारा निर्देशित हो;

(ख) किसी संदेशवाहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहुँचाना;

(ग) पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा;

(घ) उन मामलों में, जहाँ आयोग का यह समाधान हो गया है कि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त प्रकार से नोटिस, अदेशिका इत्यादि तामील करना व्यावहारिक नहीं है, समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा;

(ङ) किसी अन्य प्रकार से जिसे आयोग उचित समझे।

(2) प्रत्येक मामले में आयोग यह निर्णय करने का हकदार होगा कि कौन व्यक्ति इस प्रकार के तामील के प्रकाशन का व्यय वहन करेगा।

43. कोई नोटिस या आदेशिका, जिसकी तामील की जानी आवश्यक है या किसी व्यक्ति को पहुँचाई जानी है उस व्यक्ति या तामील स्वीकार करने के लिए उसके द्वारा दिए गए पते पर या उस स्थान पर जहाँ वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता प्रायः रहता है या व्यापार करता है या व्यक्तित्व रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, भेजी जा सकेगी।

44. उस दशा में जब आयोग के समक्ष कोई मामला लम्बित हो तथा तामील किए जाने वाले व्यक्ति ने किसी अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि को मामले में प्रस्तुत होने या स्वयं को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर दिया हो तो अभिकर्ता या प्रतिनिधि को सभी मामलों में संबंधित पक्षकार की ओर से नोटिस तथा आदेशिकाएँ तामील हाने के लिए सशक्त समझा जाएगा तथा ऐसे अभिकर्ता या प्रतिनिधि को की गई तामील को, तामील किए जाने वाले सम्बन्धित तामील माना जाएगा।

45. जहाँ नोटिस कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दिया जाए तो वह पक्षकार तामील का शपथ पत्र आयोग में आदेशिकाओं तथा नोटिस के तामील की तारीख तथा रीति का विवरण देते हुए फाइल करेगा।

46. यदि किसी याचिका को प्रकाशित करना अपेक्षित हो तो ऐसे विनिर्दिष्ट किए जाने वाले रूप में, समाचार पत्र में ऐसी अवधि और ऐसे समय के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, जिसे आयोग निर्दिष्ट करे।

47. शुटि के नोटिस, सम्मन या आदेशिकाओं की तामील या उनके प्रकाशन के संबंध में विविधमों या आयोग के निदेशों की अनुपालना न होने पर आयोग या तो याचिका खारिज कर सकता है या ऐसे अन्य या और निदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे।

48. व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई शुटि होने की वजह से किसी तामील या प्रकाशन को अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा परंतु यह तब जबकि आयोग का यह समाधान हो गया हो कि ऐसी तामील अन्य सभी प्रकार से पर्याप्त है तथा किसी शुटि या अनियमितता के कारण कोई कार्यवाही तब तक अविधिमान्य नहीं होगी जब तक कि आयोग, किए गए आक्षेप पर यह न समझे कि उस शुटि या अनियमितता के कारण वास्तव में अन्याय हुआ है या ऐसा करने के लिए अन्य पर्याप्त कारण हो।

#### उत्तर, विरोध, आक्षेप इत्यादि को फाइल करना :

49. प्रत्येक व्यक्ति जिसे जाँच का नोटिस या याचिका जारी की गई (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रत्यर्थी कहा गया है) जो याचिका का विरोध या समर्थन करना चाहता है उत्तर और ऐसे दस्तावेजों को, जिन पर निर्भर किया गया है, सात प्रतियों में ऐसी अवधि के भीतर फाइल करेगा। फाइल किए गए उत्तर में प्रत्यर्थी जाँच के नोटिस या याचिका में दिए गए तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार, इंकार या स्पष्ट करेगा तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का भी अधिकथन करेगा जिन्हें वह मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक समझता है। उत्तर याचिका की ही रीति में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगा और शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा।

50. प्रत्यर्थी उत्तर की एक प्रति दस्तावेजों की सच्ची प्रति के रूप में सम्बन्धित रूप से सत्यापित प्रतियों के साथ याचिकाकर्ता को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को तामील करेगा तथा आयोग के कार्यालय में ऐसी तामील का प्रमाण भी फाइल करेगा।

51. जहाँ प्रत्यर्थी मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक अतिरिक्त तथ्यों का अधिकथन करता है, तो आयोग याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल उत्तर का प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकता है। उत्तर फाइल करने की ऊपर वर्णित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए लागू होती।

52. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, (ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें उत्तर मांगते हुए नोटिस, आदेशिकाएँ इत्यादि जारी की गई हैं) जो इस प्रयोजन के लिए किए गए प्रकाशन के अनुसरण में आक्षेप या टिप्पणियाँ फाइल करने का आशय रखता है, इस प्रयोजन के लिए नियत समय के भीतर आक्षेपों या टिप्पणियों का विवरण, उन्हें समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियों और साक्ष्यों के साथ आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहाड़िहित अधिकारी को पहुँचाएगा।

(2) यदि आयोग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रतिभागिता मामले की कार्यवाहियों तथा निर्णय में मदद करेगी तो आयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसमें संगम, फोरम नियमित निकाय भी सम्मिलित हैं, जिन्हें यह उपयुक्त समझे आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुज्ञा दे सकता है।

(3) जब तक कि आयोग ने अनुज्ञा न दी हो, आक्षेप या टिप्पणियाँ फाइल करने वाला व्यक्ति आवश्यक रूप से कार्यवाहियों में मौखिक निवेदन करने हेतु भाग लेने का हकदार नहीं होगा। तथापि, आयोग आक्षेपों या टिप्पणियों के निपटान के लिए कार्यवाहियों के पक्षकारों को ऐसा अवसर जिसे आयोग उचित समझे, देने के पश्चात फाइल किए गए आक्षेपों और टिप्पणियों को ध्यान में रखने का हकदार होगा।

#### मामले की सुनवाई :

53. आयोग, मामले की सुनवाई के लिए जैसा उपयुक्त समझे प्रक्रम, रीति, स्थान, तारीख निर्धारित कर सकता है।

54. (1) आयोग, पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विनियश्य कर सकता है या पक्षकारों को शपथ पत्र द्वारा या मामले में मौखिक निवेदन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(2) यदि आयोग, मौखिक निवेदन द्वारा पक्षकार को साक्ष्य देने का गिरेश देता है तो आयोग यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो दूसरे पक्षकार को साक्षी देने वाले व्यक्तियों की प्रति परीक्षा करने का अवसर दे सकता है।

(3) आयोग, यदि आवश्यक या समीक्षीन समझे तो किसी अधिकारी या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाधिकारी व्यक्ति को किसी भी पक्षकार के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए निदेश दे सकता है।

(4) आयोग पक्षकार को मामले के तर्कों या निवेदनों का लिखित नोट फाइल करने का निदेश दे सकता है।

#### आयोग की अतिरिक्त जानकारी, साक्ष्य इत्यादि पांगने की शक्तियाँ :

55. आयोग किसी भी मामले पर आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी समय पक्षकारों या उनमें से किसी एक या अधिक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे आयोग उपस्थित समझे, ऐसे दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकता है जिन्हें आयोग स्वयं को आदेशों को पारित करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन से आवश्यक समझे।

56. आयोग, साक्षी को सम्मन करने का, साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकने वाले किसी दस्तावेज या अन्य तात्पर्यक सामग्री की खोज या उसे पेश करने का, किसी कार्यालय से लोक अभिलेख मांगने का, आयोग के किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के नियंत्रण या अभिरक्षा में रखे ऐसे लेखों, वहियों या अन्य दस्तावेजों या जानकारी की, जिसे आयोग मामले में समुचित समझता है परीक्षा करने का निदेश दे सकता है।

57. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 के अनुसरण में आयोग की किसी भी कार्यवाही में जो कोई साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी कार्यवाही में प्रयोग के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह कारावास, जो सात वर्ष की अवधि तक हो सकती है तथा जुर्माने का भी दायी होगा।

58. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228 के अनुसरण में जो कोई साशय आयोग की कार्यवाहियों को अपमानित करेगा या वाधा उत्पन्न करेगा वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि छः महीने तक हो सकती है या जुर्माना जो 1000/- रु. तक हो सकता है या दोनों का दायी होगा।

#### विवादिकों का अन्यों को निर्देश करना :

59. (1) आयोग कार्यवाहियों के किसी भी प्रब्रह्म पर, मामले के ऐसे विवादिकों को, जिन्हें वह उचित समझता है, ऐसे व्यक्तियों को, जिनमें आयोग के अधिकारी और परामर्शदाता भी सम्मिलित हैं, परन्तु वे उन तक ही सीमित नहीं हैं और जिन्हें आयोग विशेषज्ञीय सलाह या राय देने के लिए अहिंत समझता है, निर्देश करने का हकदार होगा।

(2) आयोग, समय-समय पर किसी स्थान या स्थानों के गिरीक्षण के लिए तथा स्थान के अस्तित्व या स्तर या वहाँ की सुविधाओं पर रिपोर्ट देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा जिनमें अधिकारी और परामर्शदाता सम्मिलित हैं, परन्तु उन तक ही सीमित नहीं है।

(3) आयोग, यदि यह ठीक समझे तो पक्षकारों को, ऊपर (1) और (2) में पदाधिकारी व्यक्तियों के सम्मुख निर्दिष्ट मामलों पर अपने-अपने विचार प्रक्रिया करने के लिए ऐसे पेश होने का निर्देश दे सकता है।

(4) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्ट या राय मामले के रिकॉर्ड का एक भाग होगा तथा आयोग द्वारा पदाधिकारी व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट या राय की प्रतियों पक्षकारों को दी जाएँगी। पक्षकार रिपोर्ट या राय के समर्थन या विरोध में अपने पक्ष का पाठ फाइल करने के हकदार होंगे।

(5) आयोग, मामले का विनिश्चय करते समय ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट या राय, पक्षकारों द्वारा फाइल उत्तर को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो रिपोर्ट या राय देने वाले व्यक्ति की आयोग के समक्ष परीक्षा होगी।

#### पार्टी के पेश न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

60. जब कोई मामला सुनवाई के लिए लाया जाए और सुनवाई के लिए निश्चित तारीख को या सुनवाई की किसी ऐसी अन्य तारीख को जिस तक सुनवाई स्थगित हो, पक्षकारों में से कोई या उनका प्राधिकृत अधिकर्ता या प्रतिनिधि पेश न हो तो आयोग, अपने विवेकाधिकार से जब याचिकाकर्ता या उस व्यक्ति के जो आयोग को सुनवाई के लिए प्रेरित करता है, अनुपस्थित रहने पर याचिका को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकता है या एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है।

61. जब कोई याचिका व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दी जाए या उस पर एक पक्षीय विनिश्चय दे दिया जाए तो व्यक्ति, यथास्थिति, याचिका खारिज होने या एक पक्षीय विनिश्चय होने के 30 दिन के भीतर पारित आदेश को वापस करने के लिए आवेदन फाइल कर सकता है तथा यदि आयोग का यह समाधान हो जाए कि जब याचिका की सुनवाई हुई उस व्यक्ति के अनुपस्थित रहने के पर्याप्त कारण थे, तो आयोग उन शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, आदेश वापस कर सकता है।

#### आयोग के आदेश :

62. आयोग, याचिका पर आदेशों को पारित करेगा तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जो मामले की सुनवाई तथा विनिश्चय पर मतदान करते हैं, आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे।

63. आयोग द्वारा आदेशों के समर्थन में दिए गए कारण जिनमें विसम्मत सदस्य, यदि कोई है, द्वारा दिए गए कारण भी सम्मिलित हैं, आदेश का एक भाग होंगे तथा इन विनियमों के अनुसार निरीक्षण तथा प्रतियों को भेजे जाने के लिए उपलब्ध होंगे।

64. आयोग द्वारा जारी या सूचित किए गए सभी आदेश, सचिव के या अध्यक्ष द्वारा बाबत शसकत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे तथा उन पर आयोग के कार्यालय की मुद्रा होगी।

65. आयोग के सभी आदेश कार्यालय के सभी पक्षकारों सचिव के अथवा अध्यक्ष या सचिव द्वारा इस बाबत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से संसूचित किए जाएंगे।

#### कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रमाणित प्रतियों का भेजा जाना :

66. प्रत्येक कार्यालय के अभिलेखों का, केवल उन हिस्सों को छोड़कर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त हैं या अन्यथा उन्हें किसी व्यक्ति को बताया नहीं जा सकता, निरीक्षण ऐसे व्यक्तियों के, ऐसी शर्तों के, जो समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित की जाएं और जिनमें निरीक्षण के समय, स्थान और रीति तथा फीस के संदाय संबंधी शर्तें भी सम्मिलित हैं, अनुपालन के अधीन रहते हुए या तो कार्यालय के दौरान अथवा आदेश पारित हो जाने के पश्चात किया जा सकेगा।

67. कोई व्यक्ति, आदेशों, विनियोगों निदेशों और आयोग द्वारा उनके समर्थन में दिए गए कारणों की प्रतियां लेने का हकदार होगा और साथ ही ऐसे अभिव्यक्तियों, कागजातों तथा आयोग के अभिलेखों के अन्य हिस्सें की, जिनका वह फीस के संदाय पर और ऐसी अन्य शर्तों के, जिन्हें आयोग निर्देशित करे, अनुपालन करने पर, प्रतियां लेने का हकदार होगा।

#### अंतरिम आदेश :

68. आयोग, कार्यालय के किसी भी प्रक्रम में इस प्रकार के अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

#### अध्याय-3

##### विवादों का माध्यस्थम

69. अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के साथ संबद्ध मामलों के संबंध में उत्पादन क्रम्मनियों अथवा पारेषण उपयोगिताओं से अंतर्वलित विवादों का माध्यस्थम, आयोग द्वारा संबंधित व्यक्तियों में से किसी के आवेदन करने पर शुरू किया जा सकता है।

70. आयोग, संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें आयोग यह कारण बताओ नोटिस कि विवाद का माध्यस्थम क्यों न किया जाए, जारी करना उचित समझता है, नोटिस जारी करेगा।

71. आयोग ऐसे पक्षकारों की, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, सुनवाई के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि प्रस्तावित माध्यस्थम के विरुद्ध कोई कारण नहीं दर्शाया गया है विवादों या मामलों को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करने वाले आदेश पारित कर सकता है।

72. आयोग द्वारा माध्यस्थम के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जहां तक संभव हो वही होगी जो ऊपर अध्याय-2 में आयोग के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए उपबंधित है।

73. आयोग के समक्ष माध्यस्थम तथा कार्यालय की लागत का वहन ऐसे पक्षकारों द्वारा किया जाएगा तथा उत्तमी राशि में किया जाएगा जो आयोग निर्देशित करे।

#### अध्याय-4

##### अन्वेषण, जांच, जानकारी का एकप्रण आदि :

74. आयोग, निम्नलिखित के संबंध में जानकारी का एकप्रण, जांच, अन्वेषण, प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण के लिए अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने विना ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे :

- (क) आयोग, किसी भी समय अधिनियम के अधीन आयोग की अधिकारिता के भीतर किसी मामले के संबंध में सचिव अथवा एक या अधिक अधिकारियों अथवा सलाहकारों या किसी अन्य व्यक्ति को जिन्हें आयोग उपयुक्त समझता है अध्ययन, अन्वेषण या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकता है।
- (ख) आयोग, उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य निदेश, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, दे सकता है तथा ऐसी समय-सीमा विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनके भीतर रिपोर्ट अथवा जानकारी प्रस्तुत की जानी है।
- (ग) आयोग, किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने और उसकी परीक्षा अनुजात करने तथा आयोग के इस निमित विनिर्दिष्ट अधिकारी को बहिर्भाव, लेखे आदि रखने या विनिर्दिष्ट अधिकारी को जानकारी देने के निदेश जारी कर सकता है या सचिव अथवा किसी अधिकारी को ऐसे निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(घ) आयोग, किसी ऐसी जानकारी, विशिष्टियों अथवा दस्तावेजों के, जिन्हें आयोग अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में आवश्यक समझता हो, एकत्रण के प्रयोजन के लिए ऐसे निदेश, जिन्हें आयोग आवश्यक समझे, जारी कर सकता है।

(ङ) यदि प्राप्त की गई कोई रिपोर्ट या जानकारी आयोग को अपर्याप्त या अधूरी प्रतीत होती है तो आयोग या सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, अतिरिक्त जांच करने, रिपोर्ट तथा जानकारी प्रस्तुत करने के निदेश दे सकता है।

(च) आयोग, उपर्युक्त के संबंध में इस प्रकार के आनुबंधिक, पारिणामिक तथा अनुपूरक मामलों पर, जिन्हें सुसंगत समझा जाए, ध्यान देने के निर्देश दे सकता है।

75. विनियम 74 के अधीन कृत्यों के निर्वहन के संबंध में यदि आयोग उचित समझता है तो जांच का एक नोटिस जारी किए जाने और इन विनियमों के अध्याय-2 में उपबंधित रीति के अनुसार मामले पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दे सकता है।

76. आयोग, किसी भी समय, किसी संस्था, परामर्शदाता, विशेषज्ञ तथा ऐसे अन्य तकनीकी तथा वृत्तिक व्यक्तियों का, जिन्हें वह आवश्यक समझता है, सहयोग ले सकता है तथा उनकी किसी भी मामले अथवा विवादिक का अध्ययन, अन्वेषण, जांच करने तथा रिपोर्ट या रिपोर्ट अथवा कोई जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है। आयोग इस प्रकार के वृत्तियों की नियुक्ति के लिए निबंधनों एवं शर्तों का निर्धारण कर सकता है।

77. यदि उपर्युक्त विनियमों या उसके किसी भाग के निबंधनों के अनुसार प्राप्त की गई रिपोर्ट या जानकारी पर, किसी कार्यवाही में आयोग की राय अथवा दृष्टिकोण तैयार करने के लिए निर्भर किए जाने का प्रस्ताव हो तो उस कार्यवाही के पक्षकारों को रिपोर्ट अथवा जानकारी पर आधिकारिक फाइल करने तथा निवेदन करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

## अध्याय—5

### टैरिफ विनियम

78. अधिनियम की धारा 55 के साथ पठित धारा 28 के अनुसर में निम्नलिखित विनियम टैरिफ नियत करने की निबंधनों और शर्तों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आयोग, सभी संबंधित व्यक्तियों की राय पर विचार करने के पश्चात् घौरेवार निबंधनों और शर्तों को जिनमें ऊर्जा के लिए प्रभारों के निर्धारण की रीति भी सम्मिलित है, अधिसूचित करेगा।

79. (1) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन कोई उत्पादक कंपनी और उससे भिन्न कोई उत्पादक कंपनी, जो एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत उत्पादन और विक्रय की संयुक्त स्कीम आरंभ कर चुकी है या इसकी ऐसी कोई अन्यथा संयुक्त स्कीम है, आयोग द्वारा टैरिफ के लिए सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना विद्युत आपूर्ति के लिए अपने ग्राहक से कोई प्रभार वसूल नहीं करेगा।

(2) कोई भी यूटीलिटी, ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय पारेपण के लिए आयोग के साधारण या विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना कोई टैरिफ वसूल नहीं करेगा।

परन्तु यह है कि उपर्युक्त विनियम केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादक कंपनियों पर उस तारीख से लागू होंगे जिसको उपर्युक्त आयोग द्वारा प्रवर्तन के लिए अधिसूचित होंगे।

परन्तु यह और कि अधिनियम की धारा 13 के कार्यक्षेत्र में आने वाले टैरिफ संबंधी किसी भी मामले को हाथ में लेने की आयोग की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव छाले बिना केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उत्पादक कंपनियों द्वारा वसूल किए जा रहे विद्यमान टैरिफ को उपर्युक्त विनियम में यथा निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख के बाद ऐसी अवधि तक वसूल करना जारी रहेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

80. खण्ड 79 (1) में यथाविनिर्दिष्ट कोई उत्पादक कंपनी जो उत्पादक कंपनी और विद्युत क्रय करने वाले पक्षकार के बीच विद्युत आपूर्ति के लिए कोई करार किए जाने का प्रस्ताव करती है, तो वह ऐसी संविदाएं करने से पूर्व टैरिफ के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

81. आयोग, समय-समय पर अधिनियम की धारा 13(छ) की शर्तों के अनुसार विद्युत टैरिफ संबंधित मामलों मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार करेगा, जिन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

82. उत्पादन और पारेपण यूटीलिटीज के टैरिफ विनियमन करने की आयोग की शक्तियों की व्यापकता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव छाले, आयोग टैरिफ अवधारित करते समय निम्न घटकों को ध्यान में रखेगा :—

(क) टैरिफ समायोजन को नियोजित पूँजी की उत्पादकता बढ़ाने और कार्यकुशलता सुधारने के साथ जोड़ने की आवश्यकता ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके;

(ख) उत्पादन तथा पारेपण की वास्तविक लागत के आधार पर टैरिफ को व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता;

(ग) लागतों के पूल को तोड़ना ताकि लागतों का व्यवस्थित आबंटन किया जा सके;

(घ) उत्पादन तथा पारेषण की कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा सेवा के स्तरों के उन्नयन में सतत वृद्धि के लिए निष्पक्ष रीति से पारदर्शी रूप में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता ;

(ङ) जहां आजार विद्यमान नहीं है वहां प्रतिस्पर्द्धात्मक परिस्थितियों का अनुरूपण तथा प्रगामी प्रतिस्पर्द्धात्मक परिस्थितियों में कार्य आरंभ करना ;

(च) पर्यावरणीय मानकों को कम से कम लागत में अपनाना ;

(छ) सभी यूटीलिटीयों के लिए एक स्तर के ही कार्यक्षेत्र का उपबंध करना ताकि उत्पादन तथा पारेषण में निजी क्षेत्र के प्रगामी समावेश को बढ़ावा दिया जा सके ; तथा

(ज) उद्योग के अनुकूल विकास की आवश्यकता ।

83. आयोग, केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी को संदेश प्रभारों के विनियमन के साथ ही अंतर्राज्यीय विद्युत नियंत्रण के लिए अन्य पारेषण यूटीलिटिज को संदेश प्रभारों का भी विनियमन करेगा ।

84. आयोग, बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए उत्पादन और पारेषण यूटीलिटीज के लिए समुचित प्रोत्साहन स्कीमें तैयार कर सकता है, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकेगा ।

85. आयोग, यदि समुचित समझे तो टाइम ऑफ डे मीटिंग (टी ओ डी) और बिलों के समय पर भुगतान के लिए स्वतः प्रोत्साहन वाली संदाय शर्तों जैसे कारणों से जुड़े विशेष टैरिफ का अनुमोदन कर सकता है ।

86. विद्युत उत्पादन अथवा उसका पारेषण करने में संलग्न यूटीलिटीज, जिन्हें आयोग से अपना टैरिफ अनुमोदित करवाना अपेक्षित है, आयोग द्वारा अधिसूचित नियंत्रणों और शर्तों के आधार पर टैरिफ प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे आयोग द्वारा विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी ।

87. विनियम 93 के अनुरूप उत्पादन या पारेषण के अनुमोदन अथवा पुनरीक्षण के लिए सभी याचिकाएं, आयोग द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी और वे इन विनियमों के अध्याय 2 में विहित याचिकाओं से संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप भी होंगी ।

88. आयोग प्रस्तावित टैरिफ, ऐसे अनुबंधों के आधार पर अनुमोदित कर सकता है जो उपयुक्त समझे जाएं और जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं । अनुमोदन की शर्तों में एक शर्त सदैव यह रहेगी कि उत्पादक कम्पनियां या पारेषण यूटीलिटीज के बीच टैरिफ से संबंधित किसी मामले से जुड़ा कोई भी विवाद आयोग द्वारा माध्यस्थित के अधीन होगा ।

89. आयोग संबंधित यूटीलिटीज की बहियों तथा अभिलेखों की जांच याचिकाका के लंबित रहने के दौरान या अन्यथा रूप से किसी भी समय अपने अधिकारियों और/या भरपूरशादाताओं से करा सकता है । अधिकारियों/भरपूरशादाताओं की रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें विनियम 59 में यथा-विहित ढंग से रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया करने का अवसर दिया जाएगा ।

90. संबंद्ध उपयोगिताएं ऐसी रीति से टैरिफ प्रकाशित करेंगी जैसी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । इस प्रकार प्रकाशित टैरिफ तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि कोई संशोधन आयोग द्वारा अनुमोदित होकर प्रकाशित न हो जाए ।

91. आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से भिन्न टैरिफ वसूल करते हुए पाई जाने वाली किसी भी उपयोगिता के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने आयोग के निदेशों का पालन नहीं किया है और वह अन्य किसी अधिनियम के अधीन दायी अन्य किसी कार्यवाही या शास्ति के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 45 के अधीन शास्तियों का दायी होगा । किसी वर्ष में किसी उपयोगिता द्वारा टैरिफ के किसी अतिरिक्त प्रभार के संबंध में आयोग के निदेशों के अनुसार कार्यवाई की जाएगी ।

92. जब आयोग स्वतः ही इस संबंध में संतुष्ट हो जाएगा कि किसी उपयोगिता के टैरिफ की पुनरीक्षा की जरूरत हो गई है तो आयोग यथा-विहित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया को शुरू करेगा । टैरिफ की स्वतः पुनरीक्षा की कार्यवाहियां वहीं होंगी जैसी कि इन विनियमों के अध्याय-2 में दी गई हैं ।

93. टैरिफ पर आयोग के आदेशों की पुनरीक्षा, इसमें सुसंगत विनियम में यथा-विहित पुनरीक्षा शास्ति करने वाले सुसंगत विनियमों के अनुसार ही स्वीकार की जाएगी ।

94. उपयोगिताएं यथा-विहित आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करेंगी जिनमें परिवासीय और लागत डाटा निहित होगा जिससे आयोग अपने आदेश के कार्यान्वयन का मानीटर कर सके और उस आधार का पुनः भूल्यांकन कर सके ।

#### अध्याय—6

योजना, विकास और विद्युत प्रणाली के एकीकृत प्रभालन तथा पारेषण अनुज्ञापि की भंजूरी से संबंधित साधारण नियम :

95. आयोग किसी यूटीलिटी को तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगा और आयोग योजना, विकास, संबंधित/अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली तथा एकीकृत प्रभालन से संबंधित कोड का अनुमोदन करेगा तथा पारेषण अनुज्ञापि प्रदान करेगा जिसे भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) के रूप में अधिसूचित किया जाएगा ।

96. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (यथा-संशोधित) की धारा 27 (ग) के अधीन पारेषण अनुशासित प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) में विनिर्दिष्ट मार्गादर्शी सिद्धांतों का पालन करना होगा।

97. कोई भी पक्षकार जो विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 27 (ग)(4) के अधीन अनुमोदनार्थ आवेदन पर केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के विनियोग से व्यक्ति हो अथवा केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता की ओर से किए गए अत्यधिक विलम्ब की शिकायत करता हो, तो वह अनुमोदन के इन्कार करने के यथा-स्थिति 30 दिनों के भीतर अथवा आवेदन प्रस्तुत करने के 60 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

98. उपरोक्त विनियम में विनिर्दिष्ट अपील के लिए याचिका उसी प्रकार फाइल की जाएगी जैसी उन विनियमों के अध्याय 2 के अधीन उल्लिखित है तथा आयोग द्वारा किसी याचिका का निपटारा इन विनियमों के अध्याय-2 के उपबंधों में दी गई रीति से किया जाएगा।

99. आयोग ममुचित परिस्थितियों को लागू करने, कार्यकुशलता में सतत वृद्धि तथा सुचारू एकीकृत प्रचालन के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिताओं को समय-समय पर उपयुक्त निर्देश जारी करेगा।

100. (1) ग्रिड प्रबंधन में केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता तथा घटकों के साथ-साथ अन्य संबंधित, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के विनियमन के कर्तव्य के निर्वाह में आयोग के विनियमों तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(2) आयोग अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनियमों तथा दिशा निर्देशों को जहां तक उनका संबंध अंतर्राज्यीय विद्युत प्रणाली प्रचालन या ग्रिड प्रचालन मामलों से संबंधित है वहां विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार समय-समय पर क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों अथवा राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्रों अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी; परिवर्तन के बिना अथवा परिवर्तन करके जैसा आयोग उचित समझता है, लागू करने का हकदार होगा।

(3) आयोग, उपरोक्त खंड (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में या तो स्वतः ही अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन या शिकायत पर कार्यवाही शुरू कर सकता है।

परन्तु यह कि मामले अगर विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 55 की उप-धारा (9) के अधीन आते हैं तो आयोग तत्संबंधी आवेदनों या शिकायतों को प्रायः तब तक स्वीकार नहीं कर सकता अथवा कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता जब तक इसे विनिर्दिष्ट विवाद्यक पर प्राधिकरण का निर्णय नहीं हो जाता या प्राधिकरण को विवारार्थ मामलों को भेजने के पश्चात् तीन महीने की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।

## अध्याय 7

### प्रक्रीण

#### याचिकाओं के निपटान की समय-सीमा

101. आयोग सामान्यतः याचिकाओं का अंतिम निपटान छः माह के भीतर कर सकता है।

#### सलाहकार समिति :

102. (1) इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन परिकल्पित सलाहकार समिति में 31 से अनधिक सदस्य होंगे जो आयोग द्वारा यथा-निर्णीत तथा इस अधिनियम में यथा-उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे और सदस्यों का कार्यकाल आयोग द्वारा यथा-निर्णीत तथा अधिसूचित के अनुसार होगा।

(2) यह आयोग समिति के सदस्यों को खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा ऐसे भर्ते/फीस का संदाय कर सकता है जो आयोग समय-समय पर विनियोग से उत्पन्न हो।

#### विनियोगों, निर्देशों और आदेशों का पुनरीक्षण :

103. (1) आयोग, किसी भी समय पर स्वतः ही किसी संबंधित व्यक्ति अथवा पक्षकार की याचिका पर, किसी विनियोग, निर्देश या आदेश की पुनरीक्षा कर सकता है और जो भी आदेश वह उचित समझे उसे पारित कर सकता है।

(2) ऐसे पुनरीक्षण के लिए याचिका उसी रीति से फाइल की जाएगी जैसा इन विनियमों के अध्याय 2 के अधीन उल्लिखित है।

#### मृत्यु आदि के बाद कार्यवाही जारी रखना :

104. (1) जहां किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए अथवा वह दिलालिए के रूप में न्यायनिर्णित हो जाए या किसी कंपनी के मामले में वह कंपनी बंद हो जाए, तो कार्यवाहियां उत्तराधिकारी के साथ से ही जारी रहेंगी जैसे संबंधित पक्षकार का कार्यपालक, प्रशासक, प्राप्तकार्ता, परिसमाप्तक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि के समय जारी रहती हैं।

(2) आयोग रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से, कार्यवाहियों को उस स्थिति में उपसमनित समझेगा यदि आयोग ऐसा निदेश देता है और मामले के रिकार्ड में अगले हित उत्तराधिकारी आदि को रिकार्ड में लाना चाहता है तो इस प्रयोजनार्थ याचिका उस घटना से 90 दिन के भीतर फाइल की जाएगी जिसके संबंध में अगले उत्तराधिकारी को रिकार्ड में लाने की जरूरत है।

### जनता को बताई जाने वाली कार्यवाहियाँ :

105. आयोग के समक्ष की जा रही कार्यवाहियाँ जनता के लिए खुली होंगी।

परन्तु आयोग, यदि उचित समझे, और कारणों को लेखबद्ध करते हुए, किसी विशिष्ट मामले की कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश कर सकता है कि जनसाधारण अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रवेश सीमित होगा।

106. (1) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228 के अनुसार जो कोई भी साक्षय आयोग का अपमान करता है अथवा आयोग की कार्यवाहियों में व्यवधान उत्पन्न करता है उसे छ: मास तक की अवधि के साधारण कारावास अथवा जुर्माने से जो 1000 रु. तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1974 की धारा 345 के अनुसार, जो कोई भी आयोग का अपमान करता है अथवा आयोग के समक्ष में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, आयोग उस अपराधी को अभिरक्षा में रख सकता है और पीठ के उठने से पूर्व उसी दिन किसी भी समय अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराधी को कारण बताने का समुचित अवसर देने के बाद कि उसे इस धारा के अधीन दण्डित कर्यों न किया जाए, उस पर 200 रु. से अनधिक की राशि का जुर्माना कर सकता है तथा जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे एक मास तक के साधारण कारावास की सजा दे सकता है जब तक ऐसा जुर्माना जल्दी अदा न किया जाए।

107. यदि आयोग उपर्युक्त विनियम में यथा निर्दिष्ट किसी भी मामले में यह समझता है कि उसके अधीन निर्दिष्ट अपराधों में से किसी भी अपराध में आरोपित किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उसे जुर्माने के भुगतान में छूक करने पर अन्यथा कारावास की सजा दी जाए अथवा उस पर कारावास के साथ 200 रु. से अधिक जुर्माना किया जाए अथवा आयोग का किसी अन्य कारण से यह विचार है कि मामले को विनियम 106 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए, तो वह उस मामले को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जो उसके विचारण हेतु अधिकृत है और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की पेशी के लिए सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत हो सकती है अथवा यदि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेजा जाएगा।

### याचिका का प्रकाशन:

108. (1) जहां कोई आवेदन, याचिका अथवा अन्य सामग्री इस अधिनियम या इन विनियमों के अधीन या आयोग के निदेशों के अनुसार प्रकाशित की जानी अपेक्षित हो तो जब तक कि आयोग अन्यथा रूप से आदेश न दे या अधिनियम अथवा विनियम में अन्यथा रूप में व्यवस्था न की गई हो, उसे सुनवाई की निर्धारित तारीख से 7 दिन से पूर्व प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे प्रकाशनों का शीर्षक ऐसा होगा जिनमें सामग्री का विषय संक्षेप में वर्णित होगा।

(3) प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे प्रकाशन इस प्रयोजनार्थ आयोग के पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

### आयोग के अभिलेखों और उनकी गोपनीयता का निरीक्षण:

109. (1) आयोग के अभिलेख उन हिस्सों को छोड़कर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं फीस के संदर्भ और ऐसी शर्तों के जिन्हें आयोग निर्देशित करके अनुपालन के अधीन रहते हुए सभी के द्वारा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) आयोग उन निम्नधनों और शारीर पर, जिन्हें आयोग उपयोग समझे, उसके पास उपलब्ध दस्तावेजों और कागजातों की प्रगमित प्रतियाँ की किसी व्यक्ति को प्रदाय की व्यवस्था कर सकता है।

(3) आयोग, आदेशानुसार यह निदेश दे सकता है कि कोई सूचना, दस्तावेज और अन्य कागजात तथा सामग्रियां आयोग अथवा उसके किन्हीं अधिकारियों, परामर्शदाताओं, प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएं या अन्यथा रूप से उनके कब्जे में या अभिरक्षा में आ जाएं, वह गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होगा और निरीक्षण या प्रतियों के प्रदाय हेतु उपलब्ध नहीं होगा और आयोग यह भी निर्देश दे सकता है कि ऐसे दस्तावेज, कागजात अथवा सामग्री का प्रयोग सिवाय आयोग द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अवस्था के किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा।

### प्रक्रिया पर आदेशों और निदेशों का जारी करना:

110. आयोग इस अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समय-समय पर विनियमों के कार्यान्वयन तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विधिध सामलों के संबंध में, जिसके लिए इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने या निदेशित करने के लिए सशक्त किया गया है, आदेश और कार्य निदेश जारी कर सकता है।

### आयोग की अंतर्निहित शक्ति की व्यावृत्ति:

111. इन विनियमों से ऐसा कुछ भी नहीं समझा जाएगा जो आयोग की ऐसी अंतर्निहित शक्ति को न्यायिक दृष्टि से आवश्यक आदेश देने या आयोग की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए सीमित करता हो या अन्यथा प्रभाव छापता हो।

112. इन विनियमों में, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप ऐसी किसी प्रक्रिया ही अपनाने से आयोग पर कोई वर्जन नहीं होगा जो इन विनियमों के किसी उपबंध से मतभेद रखते हों, यदि आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत और लिखित में अभिलेख किए जाने वाले कारणों से ऐसे मामले या मामलों के वर्ग पर विचार करना आवश्यक या समीचीन समझा है।

113. इन विनियमों में, स्पष्ट रूप से या विविक्षित रूप से आयोग पर इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी मामले पर कार्रवाई करने या ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करने पर कोई वर्जन नहीं होगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कृत्यों के संदर्भ में वह कार्रवाई कर सकता है, जो वे उचित समझे।

### संशोधित करने की साधारण शक्ति:

114. आयोग, किसी भी समय और लागत के बारे में ऐसी शर्तों पर या अन्यथा ऐसा भी वह उपचार समझे, उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी त्रुटि या गलती के संबंध में संशोधन कर सकता है और सभी आवश्यक संशोधन, कार्यवाहियों में उत्पन्न विवाद्यक या वास्तविक प्रश्न के अवधारण करने के प्रयोजन के लिए बनाएगा।

### कठिनाइयों दूर करने की शक्ति:

115. यदि इन विनियमों के किसी भी उपबंध को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकता है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप असंगत नहीं है, जो ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है।

### विहित समय का विस्तारण या संक्षेपण:

116. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी भी कार्य को करने के लिए इन विनियमों द्वारा या आयोग के आदेश द्वारा विहित समय को बढ़ाया जा सकता है (भले ही वह पहले समाप्त हो गया हो या नहीं) या उस समय को आयोग के आदेश द्वारा पर्याप्त कारण से कम किया जा सकता है।

### अनुपालन करने का प्रभाव:

117. इस विनियमों की किसी अपेक्षा का अनुपालन में असफलता तब तक केवल ऐसी असफलता के कारण किसी कार्यवाही को अविधिमान्य घोषित करेगी जब तक कि आयोग इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि ऐसी असफलता के कारण न्याय की हत्या हुई है।

### लागतें:

118. (1) ऐसी शर्तों और सीमा के अध्यधीन रहते हुए, जो आयोग द्वारा निदेशित किए जाएं, सभी कार्यवाहियों और अनुयंगिक कार्यों की लागत आयोग के विवेकानुसार प्रदान की जाएंगी और आयोग को यह अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि किसे या किस निधि से और कितनी मात्रा तक लागतों का संदाय करना है और उसे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देने का पूरा अधिकार है।

(2) लागतों का संदाय आदेश करने की तारीख से 30 दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जिसे आयोग आदेश के द्वारा निदेशित करे। आयोग का, लागतों का अधिनियम के आदेश का पालन सिविल न्यायालय की छिक्री/आदेश के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

### आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रबर्तन:

119. सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रबर्तन और अनुपालन, इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाए और यदि आवश्यक हो तो निदेशों के लिए आयोग का आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

प्रस्तुप-1

**कार्यवाही के लिए साधारण शीर्षक**  
**(विनियम 28 देखें)**  
**केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष नई दिल्ली**

फाइल करने की संख्या :  
 मामला संख्या :  
 (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित के मामले में :—

(याचिका या आवेदन-पत्र के प्रयोजन का आधार)

और

निम्नलिखित के मामले में :—

(आवेदनकर्ता/याचिकाकर्ता के नाम और पूरा पता तथा प्रत्यार्थी के नाम और पूरा पता)

प्रस्तुप-2

(विनियम 29 देखें)

**केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष नई दिल्ली**

फाइल करने की संख्या : .....  
 मामला संख्या : .....  
 (कार्यालय द्वारा भरा जाए)

निम्नलिखित के मामले में :—

(याचिका या आवेदन-पत्र के प्रयोजन का आधार).

और

निम्नलिखित के मामले में :—

(याचिकाकर्ताओं/आवेदकों के नाम और पूरा पता तथा प्रत्यार्थी के नाम और पूरा पता)

याचिका/उत्तर/आवेदन का सत्यापन करने वाला शपथ-पत्र

मैं (नाम) ..... सुपुत्र ..... आयु ..... का निवासी सत्यानिष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ और निम्नलिखित रूप में कथन करता हूँ :

1. मैं याचिकाकर्ता/आवेदक/प्रत्यार्थी आदि हूँ या मैं उपर्युक्त मामले में ..... याचिकाकर्ता/आवेदक/प्रत्यार्थी का निदेशक/सचिव/भागीदार हूँ तथा मुझे उक्त याचिकाकर्ता/आवेदक/प्रत्यार्थी ने यह शपथ-पत्र देने के लिए सम्मान रूप से प्राधिकृत किया हुआ है।

2. याचिका/आवेदन/उत्तर के पैरा ..... में दिया गया कथन अब मुझे दर्शित किया गया है और अक्षर “अ” के साथ चिह्नित किया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और पैरा ..... में दिया गया कथन मेरी जानकारी पर आधारित है और मुझे विश्वास है कि वह सत्य है।

आज तारीख ..... को स्थान ..... पर सत्यानिष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ कि उपर्युक्त शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और न ही इसमें कुछ छिपाया गया है।

मेरे समक्ष निम्नलिखित द्वारा पहचाना गया:

संजीव एस. अहलुवालिया, सचिव

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1999

No. 8/1/99-CERC.— In exercise of the powers conferred on it by Section 55 of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (Act 14 of 1998) the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely:

## CHAPTER I

## GENERAL

**Short title, commencement, and interpretation**

- (1) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- (3) They extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

**Definitions**

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:
  - 'Act' means the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (Act 14 of 1998)
  - 'Commission' means the Central Commission constituted under the Act;
  - 'Officer' means an officer of the Commission;
  - 'Petition' means and includes all petitions, applications, complaints, appeals, replies, rejoinders, supplemental pleadings, other papers and documents;
  - 'Proceedings' mean and include proceedings of all nature that the Commission may hold in the discharge of its function under the Act;

- (f) 'Regulations' means these Regulations;
- (g) 'Secretary' means the Secretary of the Commission.
- (2) Words or expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act shall bear the same meaning as in the Act.
- (3) The provisions of the General Clauses Act, 1897 as amended from time to time shall apply to these Regulations.

### **Commission's office, office hours and sittings**

- 3. The place of the offices of the Commission may from time to time be specified by the Commission, by an order made in that behalf.
- 4. Unless otherwise directed, the headquarters and other offices of the Commission shall be open daily except on Saturdays, Sundays and Central Government holidays notified by the Central Government. The headquarters and other offices of the Commission shall be open at such times as the Commission may direct.
- 5. Where the last day for doing of any act falls on a day on which the office of the Commission is closed and by reason thereof the act cannot be done on that day, it may be done on the next day on which the office is open.
- 6. The Commission may hold sittings for hearing matters at the headquarters or at any other place on days and time to be specified by the Commission.

### **Language of the Commission**

- 7. Unless otherwise permitted by an order of the Commission, the Proceedings of the Commission shall be conducted in English/Hindi.
- 8. No Petition, documents or other material contained in any language other than English or in Hindi if permitted by the Commission, may be accepted by the Commission, unless the same is accompanied by a translation thereof in English/Hindi.
- 9. Any translation which is agreed to by the parties to the Proceedings or which any of the parties may furnish with an authenticity certificate of the person who had translated to English/Hindi, may be accepted by the Commission as a true translation.
- 10. The Commission in appropriate cases may direct translation of the petition, pleadings, documents and other material to English by an officer or person designated by the Commission for the purpose.

## Commission to have seal of its own

11. There shall be a separate seal indicating that it is the seal of the Commission.

## Officers of the Commission

12. (1) The Commission shall have the power to appoint Secretary, officers and other employees for discharging various duties. It may also prescribe the qualifications, experience and other terms and conditions for the appointment of such officers and other employees.

(2) The Commission may appoint Consultants to assist the Commission in the discharge of its functions. The terms and conditions of appointment of Consultants shall be determined by the Commission at its meetings from time to time.

13. (1) The Secretary shall be the Principal Officer of the Commission and shall exercise his powers and perform his duties under the control of the Chairperson.

(2) The Commission in discharge of its functions under the Act, may take such assistance from the Secretary as it may deem fit and the Secretary shall be bound to assist the Commission.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the above provisions, the Secretary shall have the following powers and perform the following duties, viz.:

- (a) he shall have custody of the records and the seal of the Commission;
- (b) he shall receive or cause to receive all petitions, applications or references pertaining to the Commission;
- (c) he shall prepare or cause to be prepared briefs and summaries of all pleadings presented by various parties in each case before the Commission in the discharge of its function in this regard;
- (d) he shall assist the Commission in the proceedings relating to the powers exercisable by the Commission;
- (e) he shall authenticate the orders passed by the Commission;
- (f) he shall ensure compliance of the orders passed by the Commission; and
- (g) he shall have the right to collect from the Central Government or other offices, companies and firms or any other party as may be directed by the

Commission, such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Commission under the Act and place the said information before the Commission.

14. The Commission may delegate to its officers such functions including functions that may be required by these regulations to be exercised by the secretary on terms and conditions the Commission may specify for the purpose.
15. The Secretary may, with the approval of the Commission, delegate to any Officer of the Commission any function required by these Regulations or otherwise, to be exercised by the Secretary.
16. In the absence of the Secretary, such other Officer of the Commission, as may be designated by the Chairperson, may exercise all the functions of the Secretary.
17. The Commission shall, at all times have the authority, either on an application made by any interested or affected party or suo motu, to review, revoke, revise, modify, amend, alter or otherwise change any order made or action taken by the Secretary or the Officers of the Commission, if the Commission considers the same to be appropriate.

### **Recognition for Consumer Associations**

18. (1) It shall be open to the Commission to permit any association or other bodies corporate or any group of consumers to participate in any proceedings before the Commission.  
(2) It shall be open to the Commission for the sake of timely completion of proceedings, to direct bunching up associations/groups referred to above so that they can make collective affidavits.  
(3) The Commission may as and when considered appropriate notify a procedure for recognition of associations, group, forum or bodies corporate as registered consumer association for purposes of representing before the Commission.
19. (1) The Commission may appoint any officer or any other person to represent consumers' interest if considered necessary.  
(2) The Commission may direct payment to the officer or person appointed to represent the consumers interest such fees, costs and expense by such of the parties in the proceedings as the Commission may consider appropriate.

## CHAPTER II

### GENERAL RULES CONCERNING THE PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION

#### **Proceedings etc. before the Commission**

20. The Commission may from time to time hold hearings, meetings, discussions, deliberations, inquiries, investigations and consultations as it may consider appropriate in the discharge of its functions under the Act.

#### **Quorum and Sitting in Benches**

21. The Quorum for the proceedings before Commission shall be three.

Provided that the Commission may by majority delegate the power to decide specified matters or issues to a bench consisting of two full time members, but in such instances the Chairperson or member presiding over a bench shall not exercise a second or casting vote.

Provided further that in the case of a proceeding to review any decision taken by the bench of the Commission consisting of two or for consideration of any issue which could not be decided on account of equality of votes in the Bench the matter will be considered by the Commission with a Quorum of three members.

#### **Attendance by Members and Voting**

22. No Member (including Ex-officio Member) shall exercise his vote on a decision unless he is present during all the substantial hearings of the Commission on such matter.

#### **Authority to represent**

23. A person may authorise an advocate or a member of any statutory professional body holding a Certificate of Practice as the Commission may from time to time specify to represent him and act and plead on his behalf before the Commission. The person may also appear himself or may authorise any of his employees to appear before the Commission and to act and plead on his behalf. The Commission may from time to time specify the terms and conditions subject to which a person may authorise any other person to represent him and act and plead on his behalf.

## **Initiation of Proceedings**

24. The Commission may initiate any Proceedings suo motu or on a Petition filed by any affected or interested person.
25. The notice of the initiation of the proceedings may be issued by the Commission, and the Commission may give such orders and directions as may be deemed necessary, for service of notices to the affected parties, the filing of reply and rejoinder in opposition or in support of the Petition in such form as it may direct. The Commission may, if it considers appropriate, issue orders for publication of the petition inviting comments on the issues involved in the proceedings in such form as the Commission may direct.
26. While issuing the notice of inquiry the Commission may, in appropriate cases, designate an Officer of the Commission or any other person whom the Commission considers appropriate to present the matter in the capacity of a petitioner in the case.

## **Petitions and pleadings before the Commission.**

27. All Petitions to be filed before the Commission shall be typewritten, cyclostyled or printed neatly and legibly on one side of white paper and every page shall be consecutively numbered. The Commission will accept petitions filed with a Computer Disk or through Electronic Media on such terms and conditions as the Commission may specify. The contents of the Petition should be divided appropriately into separate paragraphs, which shall be numbered serially. The Petition shall be accompanied by such documents supporting data and statements as the Commission may specify.

## **General headings**

28. The general heading in all Petitions before the Commission and in all publications and notices shall be in Form 1.

## **Affidavit in support**

29. (1) The petitions shall be verified by an affidavit and every such affidavit shall be in Form 2.
- (2) Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and address of the deponent and the capacity in which he is signing and shall be signed and sworn before a person lawfully authorised to take and receive affidavits.

(3) Every affidavit shall clearly and separately indicate the statements, which are true to the—

- (a) knowledge of the deponent;
- (b) information received by the deponent; and
- (c) belief of the deponent.

(4) Where any statement in the affidavit is stated to be true to the information received by the deponent, the affidavit shall also disclose the source of the information and a statement that the deponent believes that information to be true.

30. In accordance with section 193 of the Indian Penal Code, 1860, who ever intentionally gives false evidence in any of the proceedings of the Commission or fabricates false evidence for the purpose of being used in any of the proceedings shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

### **Presentation and scrutiny of the Petitions**

31. All Petitions shall be filed with seven copies and each set of the Petition shall be complete in all respects. The fees as may be prescribed by the Commission shall be payable along with the petition.

32. All Petitions shall be presented in person or by any duly authorised agent or representative at the headquarters or such other filing centre or centres as may be notified by the Commission from time to time and during the time notified. The Petitions may also be sent by registered post acknowledgement due to the Commission at the places mentioned above. The vakalatnama in favour of the advocate and, in the event the Petitions are presented by an authorised representative, the document authorising the representative shall be filed along with the Petition, if not already filed on the record of the case.

33. Upon the receipt of the Petition the Officer of the Commission designated for the purpose of receiving the petition shall acknowledge the receipt by stamping and endorsing the date on which the Petition has been presented and shall issue an acknowledgement with stamp and date to the person filing the Petition. In case the Petition is received by registered post the date on which the Petition is actually received at the office of the Commission shall be taken as the date of the presentation of the Petition.

34. The presentation and receipt of the Petition shall be duly entered in the register maintained for the purpose by the office of the Commission.

35. The Receiving Officer may decline to accept any Petition which does not conform to the provisions of the Act or the Regulations or directions given by the Commission or otherwise defective or which is presented otherwise than in accordance with the

**Regulations or directions of the Commission.**

Provided however no Petition shall be refused for defect in the pleadings or in the presentation, without giving an opportunity to the person filing the Petition to rectify the defect within the time which may be given for the purpose. The Receiving Officer shall advise in writing the person filing the Petition of the defects in the Petition filed.

36. A person aggrieved by any order of the Receiving Officer in regard to the presentation of the Petition may request the matter to be placed before the Secretary of the Commission for appropriate orders.
37. The Chairperson or any Member as the Chairperson may designate for the purpose shall be entitled to call for the Petition presented by the party and give such directions regarding the presentation and acceptance of the Petition as he considers appropriate.
38. If on scrutiny, the Petition is not refused or any order of refusal is rectified by the Secretary or by the Chairperson or the Member of the Commission designated for the purpose, the Petition shall be duly registered and given a number in the manner to be specified by the Commission.
39. As soon as the Petition and all necessary documents are lodged and the defects and objections, if any, are removed, and the Petition has been scrutinised and numbered, the Petition shall be put up before the Commission for preliminary hearing and admission.
40. The Commission may admit the Petition for hearing without requiring the attendance of the party. The Commission shall not, pass an order refusing admission without giving the party concerned an opportunity of being heard. The Commission may if it considers appropriate issue notice to such person or persons as it may desire to hear the petition for admission.
41. If the Commission admits the Petition, it may give such orders and directions, as may be deemed necessary, for service of notices to the respondent(s) and other affected or interested parties; for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the Petition in such form as the Commission may direct and for the petition to be placed for hearing before the Commission or a Bench, as the case may be.

**Service of notices and processes issued by the Commission**

42. (1) Any notice, process or summons to be issued by the Commission may be served by any one or more of the following modes as may be directed by the Commission:
  - (a) service by any of the parties to the proceedings as may be directed by the Commission;
  - (b) by hand delivery through a messenger;

- (c) by registered post with acknowledgement due;
- (d) by publication in newspaper in cases where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notices, processes, etc. on any person in the manner mentioned above.
- (e) in any other manner as considered appropriate by the Commission.

(2) The Commission shall be entitled to decide in each case the persons who shall bear the cost of such service/publication.

43. Every notice or process required to be served on or delivered to any person may be sent to the person or his agent empowered to accept service at the address furnished by him for service or at the place where the person or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

44. In the event any matter is pending before the Commission and the person to be served has authorised an agent or representative to appear for or represent him or her in the matter, such agent or representative shall be deemed to be duly empowered to take service of the notices and processes on behalf of the party concerned in all matters and the service on such agent or representative shall be taken as due service on the person to be served.

45. Where a notice is served by a party to the Proceedings either in person or through registered post, an affidavit of service shall be filed by such party with the Commission giving details of the date and manner of service of notices and processes.

46. Where any Petition is required to be published it shall be published in such form in the newspapers to be specified, for such duration and within such time as the Commission may direct.

47. In default of compliance with the requirements of the Regulations or directions of the Commission as regards the service of notices, summons or processes or the publication thereof, the Commission may either dismiss the Petition or give such other or further directions as it thinks fit.

48. No service or publication required to be done shall be deemed invalid by reason of any defect in the name or description of a person provided that the Commission is satisfied that such service is in other respects sufficient, and no proceeding shall be invalidated by reason of any defect or irregularity unless the Commission, on an objection taken, is of the opinion that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity or there are otherwise sufficient reasons for doing so.

**Filing of reply, opposition, objections, etc.**

49. Each person to whom the notice of inquiry or the Petition is issued (hereinafter called the 'respondent') who intends to oppose or support the Petition shall file the reply and the documents relied upon within such period with seven copies. In the reply filed, the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the notice of inquiry or the Petition and may also state such additional facts as he considers necessary for just decision of the case. The reply shall be signed and verified and supported by affidavit in the same manner as in the case of the Petition.
50. The respondent shall serve a copy of the reply along with the documents duly attested to be true copies on the petitioner or his authorised representative and file proof of such service with the office of the Commission.
51. Where the respondent states additional facts as may be necessary for the just decision of the case, the Commission may allow the petitioner to file a rejoinder to the reply filed by the respondents. The procedure mentioned above for filing of the reply shall apply mutatis mutandis to the filing of the rejoinder.
52.
  - (1) Every person who intends to file objection or comments in regard to a matter pending before the Commission, pursuant to the publication made for the purpose (other than the persons to whom notices, processes, etc. have been issued calling for reply) shall deliver to an Officer designated by the Commission for the purpose the statement of the objection or comments with copies of the documents and evidence in support thereof within the time fixed for the purpose.
  - (2) The Commission may permit such person or persons including associations, forums and bodies corporate as it may consider appropriate to participate in the proceedings before the Commission if, on the report received from the Officer, the Commission considers that the participation of such person or persons will facilitate the proceedings and the decision in the matter.
  - (3) Unless permitted by the Commission, the person filing objection or comments shall not necessarily be entitled to participate in the proceedings to make oral submissions. However, the Commission shall be entitled to take into account the objections and comments filed after giving such opportunity to the parties to the proceedings as the Commission considers appropriate to deal with the objections or comments.

**Hearing of the matter**

53. The Commission may determine the stages, manner, the place, the date and the time of the hearing of the matter as it considers appropriate.
54.
  - (1) The Commission may decide the matter on the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.

- (2) If the Commission directs evidence of a party to be led by way of oral submission, the Commission may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to cross-examine the persons giving evidence.
- (3) The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an Officer or person designated for the purpose by the Commission.
- (4) The Commission may direct the parties to file written note of arguments/submissions in the matter.

#### **Powers of the Commission to call for further information, evidence, etc.**

- 55. The Commission may, at any time before passing orders on any matter, require the parties or any one or more of them or any other person whom the Commission considers appropriate, to produce such documentary or other evidence as the Commission may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.
- 56. The Commission may direct the summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects producible in evidence, requisition of any public record from any office, examination by an Officer of the Commission the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person which the Commission considers relevant to the matter.
- 57. In accordance with the section 193 of the Indian Penal Code, 1860, who ever intentionally gives false evidence in any of the proceedings of the Commission or fabricates false evidence for the purpose of being used in any of the proceedings shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.
- 58. In accordance with Section 228 of the Indian Penal Code, 1860, who ever intentionally offers any insult or causes any interruption in any of the proceedings of the Commission, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to Rs.1,000/- or with both.

#### **Reference of issues to others**

- 59. (1) At any stage of the Proceedings the Commission shall be entitled to refer such issue or issues in the matter as it considers appropriate to persons including, but not limited to, the Officers and consultants of the Commission whom the Commission considers as qualified to give expert advice or opinion.
- (2) The Commission may nominate from time to time any person including, but not limited to, the Officers and consultants to visit any place or places for inspection and report on the existence or status of the place or any facilities therein.

- (3) The Commission, if it thinks fit, may direct the parties to appear before the persons designated in clause (1) or (2) above to present their respective views on the issues or matters referred to.
- (4) The report or the opinion received from such person shall form a part of the record of the case and the parties shall be given the copies of the report or opinion given by the person designated by the Commission. The parties shall be entitled to file their version either in support or in opposition to the report or the opinion.
- (5) The Commission shall duly take into account the report or the opinion given by the person, the reply filed by the parties while deciding the matter and if considered necessary the examination before the Commission of the person giving the report or the opinion.

#### **Procedure to be followed where any party does not appear**

- 60. Where, on the date fixed for hearing or any other date to which such hearing may be adjourned, any of the parties or his authorised agent or representative does not appear when the matter is called for hearing, the Commission may, in its discretion, either dismiss the Petition for default when the petitioner or the person who moves the Commission for hearing is in default or proceed ex-parte.
- 61. Where a Petition is dismissed in default or decided ex-parte, the person aggrieved may file an application within 30 days from the date of such dismissal or being proceeded ex parte, as the case may be, for recall of the order passed, and the Commission may recall the order on such terms as it thinks fit, if the Commission is satisfied that there was sufficient cause for the non appearance when the Petition was called for hearing.

#### **Orders of the Commission**

- 62. The Commission shall pass orders on the Petition and the Chairperson and the Members of the Commission who hear the matter and vote on the decision shall sign the orders.
- 63. The reasons given by the Commission in support of the orders, including those by the dissenting Member, if any, shall form a part of the order and shall be available for inspection and supply of copies in accordance with these Regulations.
- 64. All orders and decisions issued or communicated by the Commission shall be certified by the signature of the Secretary or an Officer empowered in this behalf by the Chairperson and bear the official seal of the Commission.
- 65. All final orders of the Commission shall be communicated to the parties to the Proceedings under the signature of the Secretary or an Officer empowered in this behalf by the Chairperson or the Secretary.

## Inspection of records of Proceedings and supply of certified copies

66. Records of every Proceeding, except those parts which for reasons specified by the Commission are confidential or privileged or otherwise not to be disclosed to any person, shall be open to inspection either during the Proceeding or after the orders have been passed, subject to such person complying with such terms as the Commission may direct from time to time including in regard to time, place, and manner of inspection and payment of fees.
67. Any person shall be entitled to obtain certified copies of the orders, decisions, directions and reasons in support thereof given by the Commission as well as the pleadings, papers and other parts of the records of the Commission to which he is entitled to inspect on payment of fee and complying with other terms which the Commission may direct.

### Interim Orders

68. The Commission may pass such interim orders as the Commission may consider appropriate at any stage of the proceedings.

## CHAPTER III

### ARBITRATION OF DISPUTES

69. The arbitration of disputes involving generating companies or transmission utilities in regard to matters connected with Clauses (a), (b) and (c) of Section 13 of the Act may be commenced by the Commission on the application of any of the persons concerned.
70. The Commission shall issue notice to the concerned person(s) and to such other persons as the Commission considers appropriate to show cause as to why the dispute should not be arbitrated.
71. The Commission may, after hearing the parties to whom notices have been issued and if satisfied that no reason or cause has been shown against the proposed arbitration, pass an order directing that the disputes or the matter be referred to arbitration.
72. The procedure for arbitration to be followed by the Commission shall be as far as possible the same as in the case of hearing before the Commission as provided for in Chapter II above.
73. The cost of arbitration and proceedings before the Commission shall be borne by such parties and in such sums as the Commission may direct.

## CHAPTER IV

### INVESTIGATION, INQUIRY, COLLECTION OF INFORMATION, ETC.

74. The Commission may make such order or orders as it thinks fit for collection of information, inquiry, investigation, entry, search, seizure, and without prejudice to the generality of its powers in regard to the following:

- (a) The Commission may, at any time, direct the Secretary or any one or more Officers or consultants or any other person as the Commission considers appropriate to study, investigate or furnish information with respect to any matter within the purview of the Commission under the Act.
- (b) The Commission may for the above purpose give such other directions as it may deem fit and specify the time within which the report is to be submitted or information furnished.
- (c) The Commission may issue or authorise the Secretary or an Officer to issue directions to any person to produce before it and allow to be examined and kept by an Officer of the Commission specified in this behalf the books, accounts, etc. or to furnish information to the specified officer.
- (d) The Commission may, for the purpose of collecting any information, particulars or documents which the Commission considers necessary in connection with the discharge of its functions under the Act, issue such directions as may be considered necessary.
- (e) If any such report or information obtained appears to the Commission to be insufficient or inadequate, the Commission or the Secretary or an Officer authorised for the purpose may give directions for further inquiry, report and furnishing of information.
- (f) The Commission may direct such incidental, consequential and supplemental matters be attended to which may be considered relevant in connection with the above.

75. In connection with the discharge of the functions under Regulation 74, the Commission may, if it thinks fit, direct a notice of inquiry to be issued and proceed with the matter in a manner provided under Chapter II of these Regulations.

76. The Commission may, at any time, take the assistance of any institution, consultants, experts and such other technical and professional persons, as it may consider necessary, and ask them to study, investigate, inquire into any matter or issue and submit report or reports or furnish any information. The Commission may determine the terms and conditions for engagement of such professionals.

77. If the report or information obtained in terms of the above Regulations or any part thereof is proposed to be relied upon by the Commission for forming its opinion or view in any Proceedings, the parties to the Proceedings shall be given a reasonable opportunity for filing objections and making submissions on the report or information.

## CHAPTER V

### TARIFF REGULATIONS

78. In pursuance of section 28 read with section 55 of the Act, the following regulations relate to the terms and conditions for fixation of tariff. In addition, the Commission shall, after considering the views of all concerned, notify detailed terms and conditions including the manner in which charges for energy may be determined.

79. (1) No generating Company, owned or controlled by the Central Government and no generating Company other than those owned or controlled by the Central Government, which has entered into or otherwise has a composite scheme for generation and sale of electricity in more than one State shall charge their customers any tariff for supply of electricity without the general or specific approval of such tariff by the Commission.

(2) No utility shall charge any tariff for the inter-state transmission of energy without the general or specific approval of the Commission.

Provided that the above regulation shall apply to the generating companies owned or controlled by the Central Government with effect from the date the above regulation will be notified for operation by the Commission.

Provided further that the existing tariff being charged by generating companies owned or controlled by the Central Government shall continue to be charged after the date of the notification as referred to in the above regulation for such period as may be specified in the notification without prejudice to the powers of the Commission to take up any matter relating to Tariff falling within the scope of section 13 of the Act.

80. Any generating company proposing to enter into any agreement for supply of electricity between the generating company and any buying party shall get the approval of the Commission for the Tariff before entering into such contracts.

81. The Commission shall frame guidelines in matters relating to electricity Tariff in terms of section 13(g) of the Act which shall be notified.

82. Without prejudice to the generality of the powers of the Commission in regulating the tariff of generation and transmission utilities, the Commission may keep in view while determining the Tariff factors such as:

- (a) the need to link tariff adjustments to increases in the productivity of capital employed and improvements in efficiency so as to safeguard the interests of the consumer;
- (b) the need to rationalise tariffs on the basis of the actual cost of generation and transmission;
- (c) the unbundling of costs so as to enable the rational allocation of costs;
- (d) the need to transparently provide the appropriate incentives, in a non-discriminatory manner, for a continuous enhancement in the efficiency of generation and transmission and upgradation in the levels of service;
- (e) the simulation of competitive conditions where markets do not exist and the progressive introduction of competitive conditions;
- (f) the least cost adoption of environmental standards;
- (g) the provision of a level playing field for all utilities so as to promote the progressive involvement of the private sector in generation and transmission; and
- (h) the need for healthy growth of the industry.

83. The Commission, besides regulating the charges payable to the Central Transmission Utility, shall also regulate the charges payable to other transmission utilities for wheeling inter-state power. It shall also regulate the charges payable to the Central Transmission Utility for wheeling power though not for inter-state transmission.

84. The Commission may work out appropriate incentive schemes for generating and transmission utilities for better performance, which shall be notified from time to time.

85. The Commission may approve differential tariffs linked to factors like time of day Metering (TOD) and payment terms with built in incentives for timely payment of bills.

86. Utilities engaged in generating or transmitting electricity who are required to get their tariff approved by the Commission, shall evolve tariff proposals based on the terms and conditions notified by the Commission and shall submit the same for approval as per procedure to be prescribed by the Commission.

87. All petitions for approval of generating or transmission tariff or revision as per Regulation 93 shall be made strictly in accordance with the guidelines and procedures prescribed by the Commission and shall also be in conformity with the requirements relating to petitions as prescribed in Chapter II of these Regulations.

88. The Commission may approve the proposed tariff on such stipulations as may be considered appropriate and as may be specified in the Order. One of the conditions of

approval shall always be that in case of any dispute involving generating companies or transmission utilities, in regard to matters connected with tariff the same shall be subject to arbitration by the Commission.

89. The Commission may get the books and records of the utilities concerned examined by its officers and/or by Consultants at any point of time during the pendency of the petition or otherwise. The report of the officers/consultants shall be made available to the parties concerned and they shall be given opportunity to react on the reports in the manner as prescribed in regulation 59.
90. The utilities concerned shall publish the tariff as approved by the Commission in the manner as may be prescribed. The tariff so published shall be in force until any amendment is approved by the Commission and published.
91. Any utility found to be charging a tariff different from the one approved by the Commission shall be deemed to have not complied with the directions of the Commission and shall be liable to penalties under section 45 of the Act, without prejudice to any other penalty to which it may be liable under any other Act. Any excess charge of tariff by any utility in any year shall be dealt with as per the directions of the Commission.
92. The Commission on its own on being satisfied that there is need to review the tariff of any utility shall initiate the process of revision in accordance with the procedure as may be prescribed. The proceedings for suo moto review of the tariff shall be the same as set out in Chapter II of these Regulations.
93. Review of orders of the Commission on tariff will be entertained strictly in accordance with the relevant regulations governing review as contained in the relevant regulation herein.
94. The utilities shall submit periodic returns as may be prescribed, containing operational and cost data to enable the Commission to monitor the implementation of its order and reassess the bases on which Tariff was approved.

## CHAPTER VI

### GENERAL RULES CONCERNING PLANNING, DEVELOPMENT AND INTEGRATED OPERATION OF POWER SYSTEM AND GRANT OF TRANSMISSION LICENCE

95. The Commission shall approve the code concerning planning, development, connection/use of Inter-State Transmission System and integrated operation and grant of transmission licence which shall be notified as Indian Electricity Grid Code (IEGC).
96. Any person proposing to obtain Transmission Licence under section 27(C) of the Electricity Supply Act, 1948 (as amended) shall follow the guidelines as indicated in Indian Electricity Grid Code (IEGC).

97. Any party, who is aggrieved by a decision of the Central Transmission Utility or who complains of inordinate delay on the part of Central Transmission Utility, on an application for approval under Section 27(C)(4) of the Electricity Supply Act, 1948 may file an appeal before the Commission within thirty days of such denial of approval or within sixty days of lodging an application, as the case may be.

98. Appeal referred to in the above Regulation shall be filed in the same manner as a petition under Chapter II of these Regulations and shall be disposed off by the Commission in the same manner as any petition in accordance with the provision contained in Chapter II of these Regulations.

99. The Commission may issue appropriate directives from time to time to Central Transmission Utility for the introduction of competitive conditions, continuous enhancement of efficiency and to enable smooth integrated grid operations.

100. (1) The Central Transmission Utility and other constituents as well as others concerned in the Grid Management shall follow the Regulations and directions of the Commission in the discharge of its function of regulating the Inter-State Transmission System.

(2) Subject to the provisions of the Act the Commission shall be entitled to enforce with or without modification as the Commission may consider appropriate the decisions, directions and orders which the Regional Load Despatch Centres or the State Load Despatch Centres or the Authority may issue from time to time in terms of the power conferred on them under section 55 of the Electricity (Supply) Act, 1948 in so far it relates to the operation of the power system or otherwise has a bearing on the interstate grid operation.

(3) The Commission may initiate a proceeding in regard to matters referred to in clauses (1) and (2) above either on its own motion or on an application or complaint by any person.

Provided that in regard to matters covered by sub-section (9) of section 55 of the Electricity (Supply) Act, 1948 the Commission may not generally entertain any application or complaint or hold any proceeding till the decision of Authority on the issues referred to it or till the expiry of a period of three months after the reference is made to the Authority, whichever is earlier.

## CHAPTER VII

### MISCELLANEOUS

#### **Time limit for disposal of petitions :**

101. The Commission may normally dispose off the petitions finally within six months of admission.

#### **Advisory Committee :**

102. (1) The Advisory Committee envisaged under Section 14 of the Act shall consist of such number of members not exceeding 31 representing the various interest as referred to in the Act, as may be decided by the Commission and the tenure of the members shall be as decided and notified by the Commission.

(2) The Commission may pay to the Members of the Committee such allowances/fees apart from reimbursement of expenses as may be decided by the Commission from time to time.

#### **Review of the decisions, directions, and orders**

103. (1) The Commission may at any time, on its own motion, or on the application of any of the persons or parties concerned, within 60 days of the making of any decision, direction or order, review such decision, directions or orders and pass such appropriate orders as the Commission thinks fit.

(2) An application for such review shall be filed in the same manner as a Petition under Chapter II of these Regulations.

#### **Continuance of Proceeding after death, etc.**

104. (1) Where in any Proceeding any of the parties to the Proceedings dies or is adjudicated as an insolvent or in the case of a Company under liquidation/winding up the Proceedings shall continue with the successors-in-interest, the executor, administrator, receiver, liquidator or other legal representative of the party concerned.

(2) The Commission may, for reasons to be recorded, treat the Proceedings as abated in case the Commission so directs and dispense with the need to bring the successors-in-interest, etc. on the record of the case.

(3) In case any person wishes to bring on record the successors-in-interest, etc. the application for the purpose shall be filed within 90 days from the event requiring the successors-in-interest to come on record.

**Proceedings to be open to public**

105. The Proceedings before the Commission shall be open to the public.

Provided that the Commission may, if it thinks fit, and for reason to be recorded in writing, order at any stage of the Proceedings of any particular case that the public generally or any particular person or group of persons shall have restricted access.

106. (1) In accordance with Section 228 of the Indian Penal Code, 1860, who ever intentionally offers any insult or causes any interruption in any of the proceedings of the Commission, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to Rs.1,000/- or with both.

(2) In accordance with section 345 of the Criminal Procedure Code, 1974, whoever intentionally offers any insult or causes any interruption in the presence of the Commission, the Commission may cause the offender to be detained in custody and may at any time before the rising of the Bench on the same day take cognizance of the offence and after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished under this section, sentence the offender to fine not exceeding Rs.200/- and in default of payment of fine, simple imprisonment for a term which may extend to one month unless such fine be sooner paid.

107. If the Commission in any case as referred to in the above Regulation considers that a person accused of any of the offences referred to thereunder and committed in its view or presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine or with a fine exceeding Rs.200/- should be imposed on him or the Commission is for any other reason of opinion that the case should not be disposed off by it under Regulation 106 may forward the case to a Magistrate having jurisdiction to try the same and may require security be given for the appearance of such person before such Magistrate or if sufficient security is not given, shall forward such person in custody to such Magistrate.

**Publication of petition**

108. (1) Where any application, petition, or other matter is required to be published under the Act or these Regulations or as per the directions of the Commission, it shall, unless the Commission otherwise orders or the Act or Regulations otherwise provide, be published not less than 7 days before the date fixed for hearing.

(2) Except as otherwise provided, such publication shall give a heading describing the subject matter in brief.

(3) Such publication to be published shall be approved by the Officer of the Commission designated for the purpose.

### **Inspection of Commission's Records and Confidentiality**

109. (1) Records of the Commission, except those parts which for reasons specified by the Commission are confidential or privileged, shall be open to inspection by all, subject to the payment of fee and complying with the terms as the Commission may direct.

(2) The Commission may, on such terms and conditions as the Commission considers appropriate, provide for the supply of the certified copies of the documents and papers available with the Commission to any person.

(3) The Commission may, by order, direct that any information, documents and other papers and materials produced before the Commission or any of its Officers, consultants, representatives or otherwise which may be, or come into, their possession or custody, shall be confidential or privileged and shall not be available for inspection or supply of copies, and the Commission may also direct that such document, papers, or materials shall not be used in any manner except as specifically authorised by the Commission.

### **Issue of orders and directions on procedures**

110. Subject to the provisions of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of the Regulations and procedure to be followed and various matters which the Commission has been empowered by these Regulations to specify or direct.

### **Saving of Inherent power of the Commission**

111. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.

112. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

113. Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

**General power to amend**

114. The Commission may, at any time and on such terms as to costs or otherwise, as it may think fit, amend any defect or error in any Proceeding before it, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue arising in the Proceedings.

**Power to remove difficulties**

115. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

**Extension or abridgement of time prescribed**

116. Subject to the provisions of the Act, the time prescribed by these Regulations or by order of the Commission for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged for sufficient reason by order of the Commission.

**Effect of non-compliance**

117. Failure to comply with any requirement of these Regulations shall not invalidate any Proceeding merely by reason of such failure unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

**Costs**

118. (1) Subject to such conditions and limitation as may be directed by the Commission, the cost of, and incidental to, all Proceedings shall be awarded at the discretion of the Commission and the Commission shall have full power to determine by whom or out of what funds and to what extent such costs are to be paid and give all necessary directions for the aforesaid purposes.

(2) The costs shall be paid within 30 days from the date of the order or within such time as the Commission may, by order, direct. The order of the Commission awarding costs shall be executed in the same manner as the decree/order of a Civil Court.

**Enforcement of orders passed by the Commission**

119. The Secretary shall ensure enforcement and compliance of the orders passed by the Commission, by the persons concerned in accordance with the provisions of the Act and Regulations and if necessary, may seek the orders of the Commission for directions.

**FORM 1****General Heading for Proceedings**  
(See Regulation 28)**BEFORE THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NEW DELHI****FILING NO.****CASE NO.**

(To be filled by the Office)

**IN THE MATTER OF:**

(Gist of the purpose of the Petition or application)

AND

**IN THE MATTER OF:**

(Names and full address of the petitioners/applicants and names and full addresses of the respondent)

**FORM 2**

(See Regulation 29)

**BEFORE THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NEW DELHI****FILING NO.****CASE NO.**

(To be filled by the Office)

**IN THE MATTER OF:**

(Gist of the purpose of the Petition or application)

**AND****IN THE MATTER OF:**

(Names and full address of the petitioners/applicants and names and full addresses of the respondent)

**Affidavit verifying the Petition/reply/application**

I, AB, son of ..... aged..... residing at ..... do solemnly affirm and say as follows:

1. I am the petitioner/applicant/respondent etc. or I am a Director/Secretary/partner ..... of..... the petitioner/applicant/respondent in the above matter and am duly authorised by the said petitioner/applicant/respondent to make this affidavit.

2. The statements made in paragraphs ..... of the Petition/applicant/reply herein now shown to me and marked with the letter 'A' are true to my knowledge and the statements made in paragraphs..... are based on information and I believe them to be true

Solemnly affirm at ..... On this day of ..... that the contents of the above affidavit are true to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom identified before me by

SANJEEV S. AHLIWALIA, Secy.